(1) of section 619-A of the Companies Act, 1956:—

(i) Fourth Annual Report and Accounts of the Film Finance Corporation Limited, Bombay, for the year 1963-64, together with the Auditors' Report on the Accounts. [Placed in Library. *See* No. LT-7225/66.]

(ii) Fifth Annual Report and Accounts of the Film Finance Corporation Limited, Bombay, for the year 1964-65, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(iii) Review by Government on the working of the Corporation for the period April, 1963 to March, 1965.

[Placed in Library. *See* No. LT-7226/66 for (ii) and (iii).]

STATEMENT GIVING REASONS FOR DELAY IN LAYING ANNUAL REPORT (1963-64) OF THE FILM FINANCE CORPORATION LIMITED, BOMBAY

SHRI RAJ BAHADUR: Sir, I also beg to lay on the Table a statement giving the reasons for the delay in the laying the Annual Report of the Film Finance Corporation Limited, Bombay, for the year 1963-64. [Placed in Library. *See* No. LT-7225/66.]

ANNUAL REPORT (1965-66) OF THE ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. SUSHILA NAYAR): Sir, I beg to lay on the Table, under Section 19 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, a copy of the Tenth Annual Report of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 1965-66. [Placed in Library. *See* No. LT-7191/66.]

NOTIFICATIONS OF THE ELECTION COMMISSION

SHRI RAJ BAHADUR: Sir, on behalf of Shri C. R. Pattabi Raman I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications of the Election Commission:—

(i) Notification S. O. No. 2213, dated the 16th July, 1966, publishing Order No. 6A, making certain corrections in the Delimitation Commission's Order No. 6 dated the 26th March, 1966, relating to the State of Gujarat.

(ii) Notification S.O. No. 2457, dated the 10th August, 1966, publishing Order No. 6B, making certain corrections in the Delimitation Commission's Order No. 6, dated the 26th March, 1956, relating to the State of Gujarat.

[Placed in Library. *See* No. LT-7240/66 for (i) and (ii).]

MOTION *RE* WIDESPREAD UNREST AMONG STUDENTS

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश): I move:

"That the situation arising out of the recent widespread unrest among students in the country be taken into consideration."

सभापति महोदय, भारत में आज जो विद्यार्थियों की स्थिति हो रही है और जो देश में उनको आन्दोलन करने को बाध्य होना पड़ रहा है और सारे देश में अव्यवस्था फैल रही है, उसके बारे में मेरा प्रस्ताव है। सभापति महोदय, जब हम भारतवर्ष का इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे यहां भारत के विद्यार्थियों की जो परम्परा थी वह थी एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा रखना, बड़ों का आदर करना, और देश भक्ति की भावना रखना, वह आज भी विद्यमान है, किन्तु हमारे देश की जो परिस्थिति है उस ने हमारे सारे भारत वर्ष के विद्यार्थियों को मजबूर कर दिया और

उनको अपनी उचित मांगे मनवाने के लिए, अपना भविष्य उज्जल करने के लिए प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ा। सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी जो अपना वक्तव्य दिया था उसमें वे स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि :

"I have basic faith in the patriotism, idealism and dynamism of the youth."

यह बात बिल्कुल सही है। आज भी हमारे यहां का युवक देशभक्त है, आज भी हमारे यहा का युवक आदर्शवादी तथा गतिमान है और हमारे देश की सेवा करते रहना चाहते है। परन्तु फिर क्या कारण है किन परिस्थितियों से वह मजबूर हो गया है कि जो आज हम अपने देश में अव्यवस्था देख रहे हैं और विद्यार्थियों में अनुशासन का अभाव है ? हमारे जवान जिन पर हमारे देश की केवल एक प्रकार की उन्नति नही, सर्वांगीण उन्नति निर्भर है, आध्यात्मिक, बौद्धिक, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से, हमारी राजनीति की दृष्टि से, और जो कि हमारे भावी भारत के निर्माता हैं, जो कि उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विद्यालयो में अध्ययन करते है, क्या कारण है कि आज उनमें ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो रही है कि आज उनकी वजह से हमारे समाज में हड़तालें, प्रदर्शन और गड़-बड़ियां चल रही हैं, लूटने, जलाने, सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनायें हो रही हैं। यह सारी अव्यवस्था का कारण क्या है ? यह अव्यवस्था केवल एक दिन की नहीं, हमारी सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि वर्षों से चली आ रही है। आजादी के बाद से इसने और व्यापक रूप धारण कर लिया है। आज से 11 वर्ष पूर्व यू० जी० सी० वे एक कमेटी बैठाई थी, उसने सिफारिश की थी कि हमारे यहां के विद्यार्थियों के लिए एक "जीन" की नियुक्ति की जानी चाहिये, जिसकी जिम्मेदारी विद्यार्थियों की तरफ ध्यान देने की और अनुशासन रखने की हो। दूसरी सिफारिश यह थी कि पन्द्रह, बीस विद्यार्थियों को एक अध्यापक से सम्बन्धित रखा जाये जो विद्यार्थियों का "डीन" के सहयोग से काम करता रहे और उनकी ठीक तरह की व्यवस्था करे। लेकिन उन सिफारिशों पर कोई, अमल नही हुआ और वे दराज में शोभायमान हो रही हैं। इसके बाद यू० जी० सी० ने 1960 में एक नयी कमेटी बनाई, और उस के कुछ सदस्य हमारे राज्य सभा के भी माननीय सदस्य है। उन्होंने भी सिफारिशें कीं, वे सारी सिफारिशें इस पुस्तक मे विद्यमान हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। वह रिपोर्ट है। "प्राबलम आफ स्टूडेन्ट इन्डिसिप्लिन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज" । उसमें सारी सिफारिशें मौजूद हैं अच्छे अच्छे लोगों ने अध्ययन करके अपनी सिफारिशें कीं। मगर हमारा शासन इतना अक्षम है कि उनको कार्य रूप में परिणत नहीं किया और अब दिन पर दिन हमारे देश की परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है, हमारे देश का युवक जिसको हम समझते हैं आदर्शवादी है, जिसको हम समझते हैं कि देशभक्त है, जिसको हम गतिशील मानते हैं आज ऐसे गलत कामो को करने के लिये मजबूर हो रहा है। यह जो हमारी अव्यवस्था है इसका कारण केवल यही मान कर चला जाये तो एकपक्षीय होगा कि वह शैक्षणिक समस्या है।

हमारे विद्यार्थियों में आज जो इस तरह की मनोवृत्ति विकसित हो रही है उसके कारण हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक। इन सारे कारणों का क्युमुलेटिव्ह इफेक्ट होकर हमारे समाज में, हमारे यहां के विद्यार्थियों में आज इस तरह की मनोवृत्ति के रूप में प्रकट होते हुए दिखाई दे रहा है। जब तक हम इसका सामूहिक रूप से इलाज न करेगे तब तक समस्या हल नहीं हो सकती। बिना उन कारणों का शोधन किये उनका इलाज नही हो सकता हम अपेक्षा करें कि एक पक्षीय कार्य करने से

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया]

हमारे यहां के विद्यार्थियों की समस्या ठीक हो सकेगी या हमारे देश की व्यवस्था ठीक हो सकेगी और जिस प्रकार हम अपने राष्ट्र को उनके माध्यम से उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं ले जा सकेंगे यह संशयात्मक हैं । इसके लिये हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का और संसद का सब से बडा कर्त्तव्य यह है कि हम उन भावी निर्माताओं को ठीक दिशा देने के लिये इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करके आगे बढ़ें और उन कारणों पर विचार करके ठीक दिशा निर्देशन दें अन्यथा जो हमारे भारतवर्ष का भविष्य है और आगे आने वाली पीढ़ी है, वह खतरे में पड जायगी, जो कि हमारे लिये गौरव की बात नहीं, हमारे लिये बिलकुल अनुचित होगा । इस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि शासन इस पर गम्भीरता से विचार करे ।

सभापति महोदय, अगर हम आर्थिक कारण को देखें तो एक आदमी कालेज से निकलने के बाद भी जब यह देखता है कि मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पायेगी, मैं खाने कमाने लायक नहीं रहूंगा, जिन मेरे पालकों ने जो हजारों रुपये खर्च किये हैं उसका कुछ हिस्सा भी न चुका सकूंगा, मैं अपने पालकों पर बर्डन के रूप में हो जाऊंगा, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है ।

हमारे देश में फैली महंगाई भी उसका एक कारण है जो हमारे सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप सारे देश में अव्यवस्था फैली हुई है । अगर लोगों की आर्थिक स्थिति खराब न होती और यह महंगाई न होती तो इतनी स्थिति खराब नहीं होती । आज जो पहले थोड़ी फीस देनी पड़ती थी वह ज्यादा देनी पड़ती है, पुस्तकों का मूल्य दुगुना तिगुना देना पड़ता है, खाने के व अन्य खर्चे ज्यादा देने पड़ते हैं और सभी चीजों की कीमत ज्यादा देनी पड़ती है । सारा बर्डन पिता पर पड़ता है और जब वे पिता से पैसे मांगने जाता है तो बढ़ती हुई महंगाई के कारण पिता के दिमाग में जो गुस्सा होता है वह बच्चों पर निकालता है और उसका परिणाम यह होता है कि आर्थिक अव्यवस्था के कारण, बढ़ती हुई महंगाई के कारण, हमारे उस विद्यार्थी के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बढता जा रहा है और उसको निश्चिन्तता नहीं है । इस लिए जब तक हम आर्थिक कारण को ठीक नहीं कर देंगे , आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर दें तब तक हम यह अपेक्षा करें कि हमारे यहां विद्यार्थी अथवा समाज ठीक दिशा में काम करें, यह तो हो नहीं सकता । कितनी योजनाएं बनाई जा रही हैं मगर ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता ही गया । आज हम देखते है हमारे देश में बेकारों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है और जो पंचवर्षीय योजना का प्रतिवेदन है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

सभापति महोदय, इन घटनाओं के सामाजिक कारण भी है; हमारे सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होते जा रहा है ।परिवर्तन भारत में विद्यार्थियों में यह परम्परा थी कि वे बड़ों का आदर करे। गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व देने की परम्परा थी । "गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रहम तस्कयै श्री गुरुवै नमः" यह परम्परा थी । गुरु की आज्ञा पर शिष्य अपना जीवन दे देते थे । पर आज शिष्य का कहना न मानने पर शिष्य अध्यापक की जान तक लेलेते हैं । उस समय गुरु और शिष्य में इतना समन्वय था कि शिष्य गुरु के माध्यम से अपने लक्ष तक पहुच जाता था और भगवान को भी प्राप्त कर सकता था । लेकिन आज देखने में यह आता है कि गुरु के प्रति शिष्य की वह श्रद्धा नहीं रही । एकलव्य से जब गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगी तो उसने अपना अंगूठा दे दिया । लेकिन आज स्थिति यह है कि अगर गुरु शिष्य की बात नहीं मानता है तो वह उसको छुरे से मारने के लिए जाता है । ऐसी स्थिति

में जो सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ है वह ठीक नहीं है। शिक्षक लक्ष विहीन है और हमारे समाज मे बड़ों के प्रति आदर की भावना खत्म होती जा रही है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो पहले हमारे देश में भावना थी कि ऐसी वृत्ति प्रदर्शित करने वाला अच्छा माना जाता था वह बनी रहे और अपने गुरु तथा बडों के प्रति आदर का भाव बना रहे तथा उनका आदर किया जाय। इसके अभाव में आज हमारे देश मे इस तरह की अवस्था बढ़ती जा रही है जिसे रोकना आवश्यक है।

सभापति महोदय, हमारे सरकार की गलत नीति के कारण भी हमारे समाज मे इस तरह की अव्यवस्था फैल रही है। आज हमारे देश में इस तरह की मनोवृति पैदा हो गई है कि अगर किसी को कोई अपनी बात मनवानी होती है तो वह एजिटेशन शुरु कर देता है और हमारी सरकार भी एजिटेशन के सामने झुक जाती है। इस बात का प्रारम्भ आन्ध्र प्रदेश में श्री राम लल पुलु के आमरण अनशन से हुआ जो उन्होने आन्ध्र के निर्माण के लिए किया था। उस समय वहां पर एजिटेशन शुरू हुआ और उन्होने अपनी आहुती आन्ध्र प्रदेश के निर्माण के लिए दे दी कि सरकार पसीजेगी और झुकेगी। सरकार उस समय झक गई; इसी प्रकार महाराष्ट्र का, पंजाब का निर्माण हुआ और उसका प्रतिबिम्ब आज हमें विद्यार्थियों के आन्दोलन में भी दिखलाई दे रहा है। अगर विद्यार्थीयों को खाना खराब मिलता है तो वे सामुहिक आन्दोलन शुरु कर देते है क्योंकि हमारी सरकार जब गलत काम करने के लिए झुक जाती है तो सही बात के लिए क्यों न झुकेगी। अगर स्कूलों में फीस बढा दी जाती है तो आन्दोलन शुरु हो जाता है क्योंकि हमारी सरकार गलत काम करने के लिए राजी हो गई है और उसने समय पर उचित माग पर ध्यान देने की आवश्यकता नही समझी। यही कारण है कि आज हम तोड़फोड़ की कार्यवाही देखते हैं और राष्ट्र की सम्पत्ति को नष्ट भ्रष्ट किया जाता है। जब लोग इस तरह की बातें करते है तब सरकार झुक जाती है और कहती है कि तुम्हारी मांग मानने के लिए तैयार है। इस तरह की जो मनोवृति हमारे देश में पैदा हो गई है उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हू कि हमारी सरकार योग्यता के आधार पर, औचित्य के आधार पर निर्णय करे। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सख्ती से दमन किया जाय। अगर सरकार इस तरह की कार्यवाही नही करेगी तो देश में जो अव्यवस्था फैली हुई है वह ठीक नहीं होगी।

सभापति महोदय, इन सारी बातो के पीछे राजनीतिक कारण भी दिखलाई देते है प्रजातंत्र मे किसी न किसी ने राजनैतिक दल का शासन तो रहेगा ही किन्तु कांग्रेस शासन ने शैक्षणिक क्षेत्र में भी अपना दखल देना शुरु कर दिया है जो अनुचित है। उसने शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन मे अपनी नीतियों के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में भी राजनीति का प्रवेश करा दिया है जिससे इस तरह की सारी गड़बड़ी पैदा हो गई है। आज राजनीति के अधार पर उपकुलपतियो की नियुक्ति की जाती है, सिनेट में राजनीतिक आधार पर नामांकन किया जाता है। कालेजों में विद्यार्थियो के प्रवेश में भी राजनीति का समावेश आ गया है और इस तरह से हमारी सरकार खराब काम करती जा रही है जिसके कारण सारे देश मे इस तरह की अव्यवस्था हो रही हो है।

इस समय हमारे देश मे जो विद्यार्थियों का आन्दोलन चल रहा है उसमे भी हमारी सरकार राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। मै आपके सामने उज्जैन का उदाहरण बतलाना चाहता हूं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया

विधान सभा मे कहा कि उज्जैन में जनसंघ इन आन्दोलनों में काम कर रहा है । मै उस समय जेल मे था और जब जेल से बाहर निकला तो मैं तुरन्त कलैक्टर महोदय से मिला और पूछा कि मैं आप से जानना चाहता हूं कि जनसंघ के कौन से आदमियों का इस आन्दोलन में हाथ है ? मैंने कलैक्टर से कहा कि मैं आपके पास इसलिए नही आया हूं कि आप उसके खिलाफ कार्यवाही न करें, मैं चाहूंगा कि आप उसको सख्त से सख्त दंड दें । मैं तो सिर्फ इसलिये आया हूं कि अगर वह मेरी पार्टी का अदमी है तो मैं उसके खिलाफ अपने दल में डिसिप्लिनरी ऐक्शन ले सकू । इसका जवाब मुझे यह मिला कि Thousand times "no" from your party'. हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्य मंत्री कहते हैं कि इन आन्दोलनों में जनसंघ का हाथ था । इस तरह से अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी के मत्थे बात मढ़ना अच्छी बात नही मालूम होती है । इससे तो अव्यवस्था देश मे बढ़ती ही चली जायेगी । मै इस तरह के एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय इस समय हमारी सरकार के प्रशासन में व्यवस्था बहुत बिगड़ती चली जा रही है जिसकी वजह से सारे देश में इस तरह की अराजकता देखने को मिल रही है । विद्यार्थियों की उचित माग का ठीक समय पर समाधान नही होता है । उनकी कोई और उचित माग है, तो उसका निर्णय ठीक समय पर नही होता है । आज देखने मे यह आता है कि इम्तहान के पहले ही पेपर आउट हो जाते है । विद्यार्थियो के डिवीजनों में गड़बड़ी होती रहती है । भिन्न भिन्न क्षेत्र मे भिन्न भिन्न डिवीजन होने की वजह से आज अव्यवस्था दिखलाई देती है । विद्यार्थियों के लिए अवास की व्यवस्था ठीक नहीं है, कोर्स के बाहर के प्रश्न रखे जाते है इस तरह की कई कठिनाइयां विद्यार्थियों की है । सरकार अपनी ईमानदारी का परिचय नही देती है तो विद्यार्थियो मे एक तरह का विद्रोह पैदा हो जाता है और वे अपना छोटा छोटा सगठन बना देते है बाद मे व्यापक रूप धारण कर लेता है । इसलिए हमारी सरकार को अपनी ईमानदारी का परिचय देना चाहिये ताकि विद्यार्थियों में उसका उचित असर पड़े ।

मैं आपके सामने कल की ही दुर्घटना की एक बात कहना चाहता हूं । कल की दुर्घटना में पहाड़ी धीरज का एक विद्यार्थी जिसका नाम श्री एस० के० जैन था, जिस के पिता का नाम कपूर चन्द जैन था, पुलिस की गोली से मारा गया और उसके पिता उसकी लाश को मुर्दखाने में रात को देख आये थे । उस समय उनसे कहा गया कि लाश को कल सबेरे ले जाना । लेकिन जब वे सवेरे जाते हैं तो लाश का कही भी पता नही चलता है और भगवान जाने कहा लाश चली जाती है । तो ऐसी स्थिति हमारे प्रशासन की हो रही है । अगर विद्यार्थी की लाश का पता नही चलेगा और उसके पिता को लाश नही दी जायेगी तो यह स्वाभाविक ही है कि विद्यार्थियो में रोष पैदा हो जाय और उसके परिणामस्वरूप रोष भड़के । इस दुर्घटना में जो दूसरे अन्य लोग मारे गये वह सरकार की अपनी गलती के कारण हुआ और उसकी सजा दूसरो को देने का सरकार की ओर से प्रयत्न किया जा रहा है । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देने का प्रयत्न करेगी तो व्यवस्था सुधरेगी

अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपके सामने उज्जैन कांड की बात कहना चाहता हूं । मैंने घायल विद्यार्थियों से बातचीत की थी तो मालूम हुआ कि उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ा गया और विद्यार्थी बेहोस हो गये और उसके बाद उन्हें कुन्दो से मारा गया

तथा दूसरी मंजिल से विद्यार्थियों को फेंका गया। वहां पर प्राध्यापकों के ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया। अब आप देख लीजिये कि अध्यापकों का भी जीवन सुरक्षित नहीं है और कालेज के प्रिमिसेज में उन्हें बूटलैग मारा जाता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब हमारी सरकार छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं देती है तो इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज हमें इस तरह की हिंसात्मक कार्यवाही के दुर्दिन देश में देखना पड़ रहा है।

मध्य प्रदेश में जो विद्यार्थियों का आन्दोलन शुरू हुआ था उसका मूल सूत्र ग्वालियर से ही शुरू हुआ। ग्वालियर की घटना इस तरह से हुई कि एक ट्रक वहां की पोलीटैकनिक इन्सटीट्यूट के खम्बे को गिरा कर भाग गया। दो विद्यार्थी रिपोर्ट करने के लिए पुलिस में जाते हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। एक लड़के को वहीं पर बिठला लिया जाता है और दूसरे को चांटा मारकर रवाना कर दिया जाता है। तब विद्यार्थी कमिश्नर के पास जाते हैं कि इस सारी घटना की जांच करायी जानी चाहिये। मगर इस चीज़ की वहां पर कोई जांच नहीं होती है और मारपीट शुरू हो जाती है और झगड़े का यही कारण बनता है। अगर देखा जाय तो इस तरह की छोटी छोटी बातों की वजह से देश का अहित होता जा रहा है क्योंकि हमारी सरकार समय पर निर्णय नहीं ले पाती है। इसी का यह नतीजा है कि आज हमें इस तरह की बातें सारे देश में देखने को मिलती हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह के शैक्षणिक कारण हैं। हमारे प्राथमिक माध्यमिक, हायर सेकेन्डरी और कालेज के विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी तरह का तालमेल नहीं है। उनको छोटे दर्जों में हिन्दी द्वारा शिक्षा दी जाती है और जब वे बड़ी कक्षाओं में चले जाते हैं तो उनकी पढ़ाई अंग्रेजी द्वारा की जाती है। इस तरह की सारी अव्यवस्था के कारण विद्यार्थी अपना दिमाग मेकअप नहीं कर पाते हैं। इसी तरह की कई कठिनाइयां है। आज विद्यार्थियों को विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि लड़कों को पढ़ना चाहिये और दूसरी तरफ उनको विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता है और प्रवेश में पक्षपात किया जाता है। मैं काशमीर का ज्वलंत उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं और इसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है। इस अखबार में लिखा है :

"Bansi Kumari Bhat becomes Shamima Banu Horrible consequences of Kashmir Admissions Policy. Eleven students of Anantnag in Kashmir—Roop Krishan Raina, Piaray Lal Koul, Kanya Lal Raina, Bansi Kumari Bhat, Oma Shri, Roop Lata Zutshi, Piaray Lal Thaploo, Mohan Lal Thaploo, Chaman Lal Koul, Roshan Lal Koul and Ashok Kumar Pandit—have embraced Islam."

वह क्यों एम्ब्रेस कर लिया, उसका सारा वर्णन इसमें दिया हुआ है। उनके एडमीशन में प्रायरिटी . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN: Which paper?

SHRI V. M. CHORDIA: "Organiser"

श्री ए० डी० मणि : 'आर्गेनाईज़र' बहुत अच्छा पेपर है।

श्री विमलकुमार मंगलालजी चौरड़िया : तो यह जो प्रायरिटी जाति के आधार पर दी जाती है उसके परिणामस्वरूप इसमें दिया है :

"Last year Government admitted students with 37% to 45% marks in preference to those who had secured 55% marks or above. This preference was shown to Muslim children and VIP children. Many students appealed to the High Court. and the State Government had to cut a very sorry figure."

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

इसमें वर्णन देते हुये वे कहते हैं कि हमारे पालकों के साथ नौकरी में सब तरह का पक्षपात किया जाता है, इसलिये हम मजबूर होकर के इसलाम ग्रहण करते हैं। इस तरह की हीन मनोवृत्ति अगर देश में चलती रही और इस तरह का पक्षपात प्रवेश में होता रहा तब भी अगर हम यह अपेक्षा करें कि समाज में कुछ नहीं होगा और समाज शान्ति से बैठेगा तो यह संभव नहीं है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे शासन को इस दिशा में भी कुछ ध्यान देना चाहिये।

हमारी स्वास्थ्य मन्त्री एक जगह मीटिंग मे थीं और वहां मैं भी था। वहां उन्होंने यह उदाहरण दिया कि मेडिकल कालेजेज में प्रविष्ट होने के लिये भी पक्षपात चलता है और मैं इसका प्रयत्न करती हूं कि वह मिटे मगर वह होता जरूर है। तो जब तक इन कारणों को ठीक नहीं किया जाय, हमारे समाज मे शान्ति स्थापित नही हो सकती है। इसलिये केवल शैक्षणिक कारणों को ही नहीं, राजनैतिक आर्थिक सामाजिक और प्रशासनिक आदि सभी कारणों का अध्ययन करके जब तक हम उनका हल नहीं करेंगे तब तक हमारे यहां ठीक व्यवस्था हो सकेगी यह सम्भव नहीं है; बल्कि स्थिति और बद से बदतर होती जाएगी। आज जो देश में हमें अराजकता का भाव दिख रहा है कि वहां पर ट्रेनें जला दीं, वहा पर मोटरें जला दीं, वहां पर प्लेटफार्म तोड़ दिये, वहां पर मकान जला दिये, यह सब हमारी सरकार की आज तक अपनाई गई गलत नीतियों के कारण है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे मन्त्री महोदय इसके बारे में कुछ सोचें और व्यापक रूप से इस पर विचार किया जाय जिससे हमारे भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले जो विद्यार्थी हैं वे ठीक बन सकें और हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सके। इसके लिये आवश्यक है कि केवल हमारी सरकार ही नही, सारे हमारे राजनैतिक दल मिल कर के इसके बारे में निर्णय लें और निर्णय ले करके एक ठोस योजना ऐसी बनायें जिसकी वजह से हमारे जो भारत के भावी निर्माता हैं उनका भविष्य खराब न हो।

अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं कुछ तात्कालिक उपाय देना चाहता हूं। सबसे पहले यह बात कहना चाहता हुं कि आज तक आपने जितनी कमेटियां बनाई और उनमें जितनी सिफारिशें की, उनको कार्यान्वित करने का कष्ट करें। उसमें किसी प्रकार हीला हवाला करने की आवश्यकता नहीं है कि पैसा नहीं है, हमारे पास साधन नही है मैंने इस कमेटी की रिपोर्ट को भी पढ़ा है मगर इसको कार्यान्वित न करने से यह किसी काम की नही रही।

दूसरा निवेदन यह है कि हमारा देश स्वतन्त्र है और विद्यार्थी भी राजनीति के ज्ञान से अनभिज्ञ नहीं रह सकते, मगर राजनैतिक दलों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये और राजनीति में उनका उपयोग हो, यह मैं उचित नहीं समझता। इसके लिये सब दलों को मिल करके निर्णय ले करके आगे बढना चाहिये जिससे हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

तीसरे मैं यह चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये, उनको पूरी आटोनामी होनी चाहिये। जब तक वहां पर उपकुलपति मांग नहीं करे, पुलिस को प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। उपकुलपति कहता है कि हम नियन्त्रण कर लेंगे लेकिन नन्दा जी की पुलिस वहां जाकर के लाठी चार्ज करती है, कमरों में घुस-घुस करके लोगों को पीटती है फिर आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वहां नियन्त्रण रहेगा। विद्यार्थी जिस उपकुलपति की श्रद्धा करते है, उसी को जब वे देखते हैं कि उसकी बात नहीं चलती तो वे भी कोई चिन्ता नही करते हैं और उसकी वजह से एजीटेशन प्रारम्भ होता है। इसलिये प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जो विद्यार्थियों

की शिकायतों को सुन करके उनका हल कर सके । जब तक यह नही होगा तब तक छोटी-छोटी बातों पर भी आन्दोलन हो सकता है । अध्यक्ष महोदय, यह आपने भी सुना होगा कि खाना ठीक नहीं मिला इसी बात को ले करके आन्दोलन कर दिया गया । कभी फीस के बारे में आन्दोलन हो जाता है । फिर हमारी सरकार कभी-कभी अपनी प्रशासनिक दुर्बुद्धि का भी उपयोग कर लेती है और उसकी वजह से सारा एजीटेशन प्रारम्भ हो जाता है । ला स्टूडेंट्स के बारे में बार कौंसिल का कुछ पता नहीं और उसके लिये बन्धन कर दिया गया कि उसकी परीक्षा देनी पड़ेगी और फिर आगे तारीख बढ़ाते गये । मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसा इंजीनियरिंग कोर्स के लिये होता है कि उनको एक साल के लिये उम्मीदवार की तरह काम करना पड़ता है उस तरह इनको भी एक साल वकीलों के साथ काम करने का मौका दिया जाय और उसके लिये किसी परीक्षा का बन्धन न रखा जावे ।

आज भी बहुत से जिन्होंने एल० एल० बी० नहीं किया है वे एल० एल० एम० करने वालों से ज्यादा कमा लेते हैं । अगर उन में योग्यता नही होगी तो वे कभी कुछ नहीं कर पायेंगे । इसलिये यह बार काउन्सिल की परीक्षा का बन्धन हटना चाहिये ।

अध्यापकों एवं प्राध्यापकों की नियुक्तियां शैक्षणिक योग्यता के साथ उनके आचरण, उनकी ईमानदारी, उनकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है इन सब बातों को ध्यान में रख कर की जानी चाहिये ताकि विद्यार्थी उनके प्रति श्रद्धा रख सकें ।

फिर उनका वेतनमान इतना अच्छा होना चाहिये कि वे समाज में समय के मान से प्रतिष्ठा का जीवनयापन कर सकें और धनाभाव से उनकी समाज मे अप्रतिष्ठा न हो ।

शिक्षा आदर्शपूर्ण हो । साथ ही विद्यार्थी को अपना जीवनयापन करने के लिये भी सक्षम बना सके । ऐसा लक्ष्य बना करके हमारी शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिये ।

अध्यापकों, प्राध्यापकों एव विद्यार्थियों के बीच सम्पर्क रहना चाहिये । आज शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या काफी है और उसी मान से शिक्षण संस्थाओं का विकास करने की आवश्यकता है । अध्यापकों और विद्यार्थियों में आपसी बातचीत का अभाव रहता है । इसलिये यह व्यवस्था भी की जानी चाहिये ।

पुस्तकालय, लेबोरेटरीज़, खेल के मैदान आदि का प्रबन्ध हो । जब इस विषय पर चर्चा होगी तो इस पर और भी कांस्ट्रीक्टिव सुझाव आयेंगे । मैंने अपने नम्र मत से जो निवेदन किया है उस पर भी ध्यान दे करके इन सारे कारणों को दूर करने के लिये कोई ठोस योजना बना करके, सर्वदलीय समिति बना करके यदि इसका ठीक हल करने की कृपा करेंगे तो लाभ होगा अन्यथा यह स्थिति बद से बदतर हो जायगी और देश में अराजकता बढ़ती जायगी । धन्यवाद ।

The question was proposed.

SHRI G. MURAHARI (Uttar Pradesh): Sir, I move:

1. "That at the end of the motion the following be added, namely:—

'and having considered the same, this House is of opinion that the following measures should be taken by Government to meet the students' problems:—

(i) compulsory and free education should be provided up to the Intermediate standard;

(ii) "fancy" schools should be abolished and uniform type of schools should be provided for all;

(iii) restrictions on admission to colleges and universities should be abolished;

(iv) education should be imparted only through the medium

[Shri G. Murahari.]

of the mother-tongue or regional language;

(v) students' unions with compulsory membership should be established;

(vi) free education up to the highest standard should be provided for the students who are socially and economically backward;

(vii) ex-Government servants and ex-Ministers should not be appointed as Vice-Chancellors and Principals;

(viii) arrangements should be made for low-cost hostels and cheap meals for the children of those persons whose monthly income is less than three hundred rupees and Government subsidy should be given for this purpose;

(ix) no restriction should be placed on political parties starting youth organisations in the universities or colleges and on the students for participating in them;

(x) arrangements should be made for providing jobs according to the aptitudes and qualifications of the students who have completed their University, College or school education;

(xi) entry of the police into temples of learning should be altogether banned;

(xii) the principle of "equal remuneration for equal service" should be immediately implemented in all government and non-government educational institutions;

(xiii) the teachers should ordinarily have the right to participate in the politics of their choice;

(xiv) the State Governments should spend 20 per cent of their budgets and the Central Government 10 per cent of its budget on education under any circumstance;

(xv) inaugural and convocation address by Ministers and government servants in the temples of learning should be strictly banned;

(xvi) special emphasis should be laid on technical education;

(xvii) an impartial judicial enquiry at the highest level should be conducted at places where firing has been resorted to in connection with the students' agitations and the officers in charge of the administration of those places should be immediately transferred;

(xviii) all the persons arrested in connection with the agitation should be released unconditionally and the cases filed and warrants issued against the student leaders should be withdrawn;"

(The amendment also stood in the name of Shri Rajnarain)

SHRI BANKA BEHARI DAS (Orissa): Sir, I move:

2. "That at the end of the motion the following be added, namely:—

'and having considered the same, this House is of opinion that a high-powered Inquiry Commission, consisting of Members of Parliament, Educationists and other eminent men under the Chairmanship of a Judge of the Supreme Court be set up to inquire into the causes of the widespread student unrest in the country'."

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal): Sir, I move:

3. "That at the end of the motion the following be added, namely:—

'and having considered the same, this House is of opinion that a permanent negotiating machinery should be set up at the Union Government level to look into the grievances of students and to serve as a means of dialogue between the representatives of students and the Government'."

The questions were proposed.

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN *(Maharashtra): Mr. Chairman, before* I make my observations on the Subject-matter of this motion, permit me to thank you, Sir for giving precedence to this motion. It shows the importance that the question of student unrest has come to assume in recent days and in our present day life. It is but natural that it should be so. Everyone of us—the parent, the teacher, the educationist, the administrator, the social and political worker —has a feeling of anxiety in each one's mind and we are pondering as to why the student of today is so uneasy and angry. Students are but hopes of tomorrow. They are the makers of democracy and the nation. They are the preservers of all the ideals that we have struggled for. And if it is found that this community is amenable or has been amenable to an anarchist way of thinking, a trend which will blast the very foundations of our democratic social fabric, where is the hope? Is it not a red signal for all of us? We have, therefore, to pause, analyse and find out real measures which will try to remove this unrest.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

The student community and the unrest in them is also a delicate question. The community, let it be understood, has both the potentialities. It catches fire like a dry stack of grass under certain conditions, but it really can be an atomic power plant useful for the healthy growth of the community as a whole. So, I expect and wish that the debate on this motion be an objective and dispassionate one. The views expressed here by Members may be critical, but there should be constructive suggestions also. Let it be noted that if we do not act jointly now, the present trends will not only mean the end of law and order and peaceful conditions of growth, but will also mean an end of what even the Opposition stands for. The problem has, therefore, to be analysed firstly from the point of view of the immediate present, *viz.*, what exactly happened during the last one or two months and, secondly, from the point of view of long-range solutions, namely, the deeper reasons behind the outbursts. I shall, first of all, give my observations about the immediate present. It is true that there have been cases of student indiscipline in the past, but they have not been so widespread and violent. What made the students almost in three or four States so angry? What were the kinds of grievances, what were the methods used? All these need to be examined and a co-ordinated picture formed. What does the factual analysis of the events that took place over the months of September and October point to? Madam, before I give out my analysis let me point out that I have prepared detailed statement of these events from the reports which have appeared in papers like the "Times of India." I have tried to read minutely the reports about all these incidents of student unrest. I am convinced that a clear picture, a clear impression can be formed only if a co-ordinated view of the events is taken. I have tried that and I am submitting in brief my observations thereon. In noting and reading these reports there might have been some mistake or omission. But this error will be the order of three per cent and not more.

Now coming to the factual analysis of what happened during the last two months, let me put it in a summary form, in brief. The analysis covers

[Shri S. K. Vaishampayen.]

incidents over a period of one and a half months.

September was a month of student unrest in Madhya Pradesh. October was a month of student trouble in U.P. and Bihar and partly in West Bengal.

In September there were altogether 48 disturbances at 40 places. Out of these only 4 disturbances had some relation with academic matters, and there were 8 other disturbances which were of a non-academic character and which were also on paltry issues.

In the first fortnight of October there were 27 disturbances at 26 places, two of the disturbances alone having some bearing on academic issues, whereas 5 disturbances were such which were non-academic and having a bearing on paltry issues.

Coming to the academic issues that were involved, what were they? In Delhi there was a demand for the abolition of the Bar Council examination. In Warangal there was a demand for the transfer of a lecturer. In Kozikode there was a demand for better hostel facilities and reduction of fees.

In Bombay there was that incident about a girl's mouth having been sealed with a sticking plaster by her teacher. At Lucknow there were demands of the Ayurvedic College students, but these demands had really no support among the student community. In Jammu there was the students' fast in the Agricultural College.

Coming to the other non-academic and paltry issues, let me enumerate them in brief before you.

In Bhopal there was a scuffle with the S.T. officers. In Srinagar the students protested and demonstrated because the police detained a lecturer, for interrogation in a sabotage case. In Sibpur, in Calcutta, there was a scuffle between students and people which took place about four days earlier. In Jaipur some articles appeared in a local paper about mismanagement of a local hospital, and therefore the students of the Medical College struck work and demonstrated and protested and there was a disturbance.

In Rohtak there was a protest against the arrest of a Jan Sangh M.L.A. In Bankura there was a hartal by the United Leftist Front and the students joined that. In Jammu there was a clash with a Minister's son and therefore the students went on a strike and protested. In Jabbalpur there was a clash with some people.

In Samastipur in Bihar, there was a fight with a cobbler for charges about boot polishing. In Sahasra the students wanted to break the C.M.'s meeting. In Calcutta there was a clash between the N.C.C. boys and the transport authorities. In Kasargode there was an agitation about the appointment of a Commission for deciding the boundary question. In Trivandrum there was a demand from the students that the pay scales of engineers of the Electricity Board should be improved.

Taking these non-academic and academic issues that were involved, we should try to deduct these from the total number of incidents that took place, and we will find that 56 disturbances that were there in the month of September and the fortnight of October were the result of the incidents which took place at Indore and Gwalior and later on at Lucknow. All the rest of the disturbances which took place at other places were merely a sort of chain reaction to the incidents that took place at Indore and Gwalior and at Lucknow. So far as these are concerned, it is also very important that we should try to know what exactly happened at Indore. At Indore a daily published a news about a scuffle between two student groups and alleged that the students of the Vaishnav College had attacked the other students with a pen-knife. The students became angry and they demanded a contradiction from the

editor. The contradiction was not given and therefore the students went and raided that particular press and attacked the editor and therefore the situation became violent. This was the whole incident and as a result of this Sec. 144 had to be promulgated by the district authorities. This news reached Gwalior and there also the whole atmosphere became tense and therefore the authorities feared that there would be some trouble and they promulgated Sec. 144. Later on the students went on defying the ban that was imposed. There were clashes, pitched battles, in Indore and Gwalior, and then later on whatever happened in other places was a sort of chain reaction to these particular incidents. Whatever incidents had taken place in U.P., the demand of the students is that the police excesses that were committed in Madhya Pradesh should be enquired into. The 56 disturbances that took place over a period of 1-1|2 months in three or four different States were the result of what happened at Indore and Gwalior. This is what made the students angry. Some of the features of these disturbances were almost of a particular pattern namely, that the processions were taken out in defiance of Sec. 144 that was promulgated or in defiance of the curfew that was there; the processionists made police vans and police chowkis their targets—that was one very significant feature of all these 56 disturbances which must be taken note of. Another feature of these demonstrations is there was damage to railway property, telephone property and other things. Here I must submit that at the three places, namely, Indore, Jaipur and Gwalior, the press there was attacked, the editors were attacked. Midnight attacks were made at Jabbalpore, Gwalior and Indore. All these must be taken note of by all of us as to why there were these disturbances, what form they took and in which direction they were led. Besides, there are two other significant facts which must be taken note of. I have gone through every report of these incidents and tried to find out how many students were injured and how many police constables were injured.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You must wind up. There are many Members who want to speak.

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: I have taken ten minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have taken fifteen minutes. You will have one or two minutes, but you must wind up.

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: What I would like to state is that an equal number of policemen were injured in all these disturbances. Secondly, as has been made clear by the Home Minister in a conference, 30 per cent of these demonstrators were students and the rest of them were other people. So, all these facts must be read together in a co-ordinated way and then we must try to find out what exactly must be done about all these things. Since there is little time before me I will be very brief in my observations. Following are some of the irresistible conclusions which emerge from the above facts:

(1) That the demonstrations or protests were not mainly for academic considerations. Only 6 out of 75 disturbances were for some demands concerning studies or facilities in colleges.

(2) That the students today have a mood which sparks off and once it is there, the same is used by unsocial or political elements and the students are led into violent situations.

(3) That there was a law and order situation and the police at a fairly large number of places interfered when the situation became violent.

(4) That entering into educational institutions by the Police unless called for by the authorities should have been avoided.

(5) That there is a master-mind behind which may be a bearded one or a bald-headed one.

[Shri S. K. Vaishampayen.]

It is therefore necessary that the students should consider whether they should agitate for non-academic issues and if at all they have to do so for their own demands, whether they should take to violent and anarchic methods.

A consultation machinery to solve the academic issues of the students should be evolved and they should be saved as promptly as possible. Further, the Home Ministry must take all preventive measures of isolating unsocial and mischievous political elements before any situation like this flares up. These are measures of an immediate nature.

The real remedy lies in going into the deeper causes and long-term solutions. We must think more seriously and with sympathy as to why the students have developed an uneasy temperament and a mood that can be easily sparked. Students are uneasy and disturbed more because there is an atmosphere of purposelessness. An environment of a dangerous vacuum is growing around them and the students are exhibiting the effects of the same. This is a result of a number of factors, social, educational, political, etc.

The students community is like a kite whose thread-line is cut and which is soaring in any direction, in whichever way a gust of wind may carry it. Is this state of affairs very happy? Shall we allow this kite to float without any direction or destination? For this sorry state of affairs we are all responsible. A students, as he is coming up, has no care of the parent, no guidance of a teacher nor any inspiration from the social life around him. This has led to a state of vacuum, uneasiness, carefree attitude and a desperate mood among the students. Let us all come together and see as parents, educationists and administrators, that this particular state of vacuum that is there in the minds of the students, which has come to stay and which has resulted in an anarchist way of thinking among them, is removed and that the student community is made to play its rightful role in the country.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): I am glad that the House is having an opportunity of discussing this situation arising from the widespread student unrest in the country. It is difficult in the course of this debate to prescribe what one may call 'readymade' solutions. It should not be exactly assumed that the student unrest is a malady for which sulpha treatment or antibiotic treatment would be immediately effective. I have been trying to study this problem in many of its facts and recently in the City of Nagpur I addressed a meeting of 800 students on this question. I have discussed this matter also with some of the so-called student leaders and individual students and I feel that the present student unrest is a heritage of the past. We had in this country always yielded to violent disturbances. If there had been any undermining of respect for law and order in this country, that undermining started from the days of the States Reorganisation Commission. The House will recall that the Government had taken a decision that the City of Bombay would be Union territory and that there would be a bilingual State of Bombay and Gujarat. This decision of the Government was defied in the streets of Bombay and the Government yielded to that agitation. There was a hunger-strike by Mr Potti Sri Ramulu of revered memory from Andhra Pradesh and the Government yielded to that agitation and announced the creation of the State of Andhra Pradesh. I am not suggesting

. . .

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): May I correct my learned friend? It was the commitment of the Congress for the last 40 years to establish that State.

SHRI A. D. MANI: I am just coming to it. I am giving a historic survey of the causes of the student unrest and the present lawlessness in the country. Government itself was undermining

respect for law and order and has made it clear to all concerned by its example that it would not take any immediate action unless there is a violent disturbance.

SHRI AKBAR ALI KHAN: We question it.

SHRI G. RAMACHANDRAN (Nominated): Why not Mr. Mani go back to the original fall of man?

SHRI A. D. MANI: I may even go back. If the hon. Minister of Education would examine the files regarding the student unrest, they were much less during the period 1947 to 1954 and after the States Reorganisation Commission from the manner in which the Government yielded to violent agitations, the Government has set a bad example of lawlessness. We cannot blame the students because they found that by leading a violent agitation they commanded greater respect. If the Government had insisted that any lawless agitation would be seriously discountenanced and that they would not take any decision under the pressure of circumstances, they would maintain respect for law and order. If the food supply at the canteen is unsatisfactory, the students feel that by staging a demonstration in Delhi they can command immediate attention to their grievances by the authorities concerned. I am afraid all of us, not only the Government but Members of the Opposition and members of political parties, are responsible for the present state of unrest among the students as well as unrest in other walks of life.

The second point that I would like to urge, Madam, is that the country is getting tired of this so-called parliamentary form of government. I am not suggesting that we should be over to a form of guided democracy or presidential type of government. But Parliament and the Legislatures have not offered any effective solution to the problems of the country. In Britain, Parliament was the result of a historical growth. Parliament was first set up to curtail the rights of the barons and we know that this was the foundation of the Magna Carta and the development of parliamentary institutions in England. But, unfortunately, here Parliament came as a readymade institution as a result of the Constitution adopted by the Constituent Assembly in 1951. This Parliament and the Legislatures in the various States, have not been effective in solving the economic problems, and the streets became the forum for parliamentary and extra-parliamentary discussions. Suppose some matter is discussed on the floor of the legislatures or on the floor of Parliament, enough attention is not given by Government, not the same kind of attention which is given to a demonstration organised outside Parliament House. It is because Parliment has not fulfilled the aspirations of the people that the people are resorting to all sorts of extra-Constitutional methods for focussing public grievances.

The third point that I would like to mention is that the student unrest is a part of the present lawlessness all over the country. Yesterday the house of our revered leader, Mr. Kamaraj Nadar, was raided by some of those people who took part in the demonstration. I want to warn the Government that a day is coming when Ministers' houses also will be raided by people . . .

1 P.M.

AN HON. MEMBER: Yesterday it was done.

SHRI A. D. MANI: . . . when people having cars and substantial private property will find hooligans marching into their houses and pulling them out. That is because there is a sense of despair in the country. The Congress is the only party which has got the organisation for governing the country. I am not a Member of the Congress, Madam. But I feel that the Congress contains a number of very good elements which can shoul-

[Shri A. D. Mani.]
der the administration and the destinies of the country.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Mysore): Question.

SHRI A. D. MANI: I am coming to that. I would like the Congress to be defeated in some States to restore democracy in the country. If democracy is to survive, the Congress Party must be defeated at the polls in some States. It is because people find that the Congress controls the purses of the people . . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN: In your State also?

SHRI A. D. MANI . . . My time is limited .....and the Congress cannot be defeated at the polls because it can command better financial resources than any other party. The people are feeling that these people are going to continue in power, that they cannot be got rid of. Some of them are persons who will never find positions in any democracy of the world but they are promoted to posts of Ministers and are holding high positions of dignity. Now we must restore the sense of balance to this democracy. I feel that the situation in the country is so grave that the Congress must not think in terms of one-party government but must think in terms of a coalition of parties to tackle the grave economic emergency facing us. It means a great sacrifice on the part of the men of the ruling party because all men cannot be accommodated in Cabinet positions. If the Congress thinks in terms of one-party Government, this kind of lawlessness will continue with unabated vigour But if other parties are allowed to take part in the Government after the elections, we may restore a sense of normalcy to the democratic structure.

Madam, I would like to go to another point. When I was a student then also there were agitations. I remember when I attended a meeting and shouted slogans, I was interrogated by the police after the meeting. In those days we had a cultural revival in the country. Those were the days when Sir C. V. Raman was about to get the Nobel Prize, when Dr. Meghnad Saha had astounded the world of science by his theories in Mathematics. That was the time when Rabindranath Tagore's poems were sung in every home. But at present there is no cultural revival in the country. And this absence of cultural revival is having its impact on the minds of the students. The students find that the lecturers who have been appointed perhaps were recruited because they happened to be influentially connected with some of the Ministers or they somehow managed to manipulate the Public Service Commission to get into service. Madam, I am shocked to say that a good part of my time is taken up in Delhi at meeting people who come to me and say, "Sir, we are appearing for interview tomorrow. Can you talk to so and so and try to see that I am selected?" And I have always said that I never interfere in such selections.

People have come to believe in this country that merit does not count, that it is influence that counts very much and it is this thing that is eroding the minds of our students. People find that the lecturers are not able to give them any attention, that the lecturers are men who have been indifferently recruited by various Public Service Commissions. Would you like to raise any objection to what I say, Mr. Minister?

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no.

SHRI A. D. MANI: I would take about five minutes more, Madam. I am developing some points.

Madam, I feel that we must also reorganise the educational structure and try to see that the tutorial system is introduced. There must be a tecaher who will be in charge of 20 or 25 students. He will not only take their classes but go to their homes and find

out what their problems are. There is no personal contact between the teacher and the taught at the present time. The absence of personal contact is seen in the indifference of the student who studies and in his behaviour outside.

Madam, I would also like to say that every college must have a bureau to advise persons regarding employment. When students find that when they come out of college they have to stand in the queue for jobs, that they have to get the influence of somebody to get themselves appointed, they get desperate. We must have employment bureaus in every University, in every college, where there will be a psychologist who will advise the students.

Further, the economic situation in the country must improve considerably if the student unrest is to abate. It is well known that many persons are maintaining students at the colleges at a great financial sacrifice. Whenever they find that the father is to cut down on medicines or on clothing in order to see that the student is sent to the college and that the father has been superseded in service because of the interventions of persons in authority, the student becomes desperate. The economic situation must improve. Prices must be controlled if the student disturbances are to come down.

Madam, I would also like the Minister to consider the practice adopted by the Oxford and Cambridge Universities of sending down students who misbehave in colleges. It is well known, as the hon'ble Minister of Education will testify, that if a student is found often drunk and going about with undesirable girls, he is straightway sent down in the Universities of Oxford and Cambridge. Can that happen in our country?

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI M. C. CHAGLA): We have the system of rustication or dismissal. It is for the Vice-Chancellor to take the action. We use the words "sending down" in Oxford. But it is open to the Vice-Chancellor who has got powers of discipline to rusticate a student for a year, for two years or permanently dismiss him. He has got all the powers. They have got to be exercised.

SHRI A. D. MANI: But there has not been one case where a student at Oxford has gone to the Queen's Bench with a writ petition as is being done in this country. You cannot rusticate a student when the matter has to go to a court of law.

SHRI M. C. CHAGLA: We have fundamental rights.

SHRI A. D. MANI: Fundamental rights are there in England also. But nobody goes to the Queen's Bench with a writ petition. Here as the hon'ble Minister of Education himself will testify, when he was the Chief Justice of Bombay, as to how many such cases he handled. There are so many persons coming up with writ petitions. You cannot rusticate students. We must give absolute power under law, if necessary, by which the Universities will be given the right to rusticate a person if he is found guilty of misconduct.

Finally, I would like the parties to come to an agreement that they will not interfere with the working of Universities, that no political leader will try to enlist the support of students for election campaigns or be associated with any student agitation. If these suggestions are accepted, probably there may be an improvement in the present situation though I do not forsee that the student unrest will disappear until and unless the economic situation improves.

AN HON. MEMBER: How long are we sitting?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Till 1.30.

SHRIMATI MOHINDER KAUR (Punjab): Madam Deputy Chairman, we are all worried about the continued

[Shrimati Mohinder Kaur]

student unrest in the country. I have just been hearing speeches. I do not know how many people have given thought to this problem because this particular phenomenon is not peculiar to India alone. You find this problem of using the youth in most of the developing countries. There are various factors which are responsible for it. Firstly, the high expectations the people had after attaining independence fell short due to the birth-rate having outstripped the pace of development in those countries. I will not go very far, Madam. I will confine myself to Asia alone. You know that in this one continent 56 per cent of the population of the world lives and you find that the youth are being exploited in several countries of this continent. I will draw your attention to our next door neighbours. What is happening in Pakistan, Indonesia, Red China? The youth are being exploited. In India too the youth are being exploited on a very large scale which we can understand because people are looking at the forthcoming general elections. Some irresponsible elements are taking advantage of the passions of the youth and trying to arouse them but I do not know whether they understand the consequences. It is easy to exploit them and arouse their passions but I really wonder as to what is the ultimate objective of rousing the passion of the youth. Is it only to create lawlessness in the country and to bring the ruling party to discredit? Perhaps the ultimate objective is to dislodge the Government but after all the country cannot be without a ruling party. Whichever irresponsible elements are doing this, I would like to say that they are playing with fire. They do not even realise the consequences of what they are doing because ultimately they will find it difficult to stem the tide. There is also the other side of the picture. When we look at the students and teachers, why are they agitated? Perhaps they also have genuine grievances. We should look into that also. I agree with the several speakers who have spoken before me. They have said that because of certain appointments that we have made in the Universities which have really not been made on merit this is happening. Most of us agree on that point because I feel that some Registrars or Vice-Chancellors are not ideally suited and I would request the Education Minister to see to it that such appointments are only made on merits and on no other consideration because if we want to find leaders to lead the students, then they must be found from within the campus of a University and not from outside from where we may like to rehabilitate some people. I am not speaking from hearsay or from newspaper reports. My work takes me to the different parts of the country. I have travelled a good deal in connection with my work. I am speaking from personal experience and from my own judgement. On several occasions I have met several of our Vice-Chancellors and I have been greatly surprised as to how they have come to occupy such positions of responsibility in this country. I very humbly submit to the Education Minister in the future to take care that Registrars and Vice-Chancellors are appointed only on merit and not on any political consideration because if such people are appointed how can we expect the students to look up to them and expect the teachers to respect them? If they cannot look up to the Vice-Chancellor or to the Registrar, how can we expect any discipline because you can only discipline a person if you command a certain respect.

Various other factors are also there. Many have suggested various reasons for the agitation. They have also suggested that there should be more spacious educational institutions, there should be extra curricular activities and the teachers should be better paid. These are justifiable demands but in a country like ours these cannot be achieved overnight, particularly with a poor economy like

ours when we are making desparate efforts to bridge the abnormal gap between supply and demand but these are ideals which we should aim at certainly when our resources permit us.

The Education Minister had appointed an Education Commission which has brought to light certain things and I hope he will implement them. One of the recommendations is that the teachers should have a better status, should receive better salaries, that their service conditions should be looked into, etc. Unless it is done this profession cannot be attractive. You look at the qualifications of the teachers but they are one of the poorest members of the society. They have to study, hard and what do they get? This profession is thoroughly unattractive and so people with the right aptitude do not come into it. So this recommendation of the Commission should be accepted by the Government and it should be implemented. I am fully aware of our economic conditions. If our finances permit, this is one of the recommendations which should be speedily implemented.

I will come to the students. In my work I have had a great deal to do with the students. I do not wish to speak about myself but I want to tell you that in the past 13 years I have had a lot to do with the students in my capicity as Chairman as well as Vice-Chairman of the Small Savings Board in Punjab. I have tried to get the cooperation of the students and I have never found them unwilling to help. Whenever I have gone to them for any constructive programme I have always found them very willing and they have helped me out a great deal. Perhaps it might interest you to know that in Punjab in 1800 institutions we have been able to implement the Savings Scheme with the help of the students. Their interest in constructive work has not vaned. If we have not channelised them for constructive work it is our fault. This is only one of the things where I tell you from experience that I have taken the cooperation of the students. Punjab is the only State where we have built up 9 lac accumulated Time deposit accounts and that has been done with the help of educational institutions and Panchayats and I have always found that whenever I have gone to the students for any constructive programme, I have received their cooperation. This is one of the fields where we should channelise their energy for any constructive work and if we do it, I am sure help will be forthcoming but we have to use our imagination. There are very many spheres where students could be easily used. For instance during their holidays, when we are laying so much stress on intensive agriculture and when Government is giving so many facilities to agriculture and India is a country where the percentage of literacy is very very low, I feel that we could utilise the students, most of them come from the rural areas, to go to the villages to see about the facilities to be given there, about loans to farmers, etc. You can channelise their energy into building up this country.

I will not take very much more of your time. I would like to complement the Education Minister for his very bold and imaginative action. He is the person who boldly set up a Commission and I am sure every rational person in this country will stand by him if he can find a remedy to this problem. There is nothing more that I have to add but I again stress that you must utilise the energy of the students because that is the only way by which we can stop all this exploitation by irresponsible elements—I would not like to use any other name except irresponsible elements—because it is only in their spare time, when they feel frustrated, that they are vulnerable to this exploitation. If we make them feel that they are members of the society, that they are citizens of this country and they also have a responsibility in this country for procreative work and build up the economy of this country, I am sure we should be able to solve this problem.

[Shrimati Mohinder Kaur.]

Lastly, I will tell you how to deal with the present discontent. I feel that in each State there should be a State level Committee to go into this problem mainly comprising of educationists and people in public life. I do not mean by that merely politicians but others also have a role to play in public life—people in cultural life, social field, etc. You should get that team together and tell them to meet the students in the Universities and colleges, wherever there is a programme for unrest. They should find out the cause of discontent, whether it is among the teachers or students. If there are any genuine grievances, then the Government should certainly look into them. I am suggesting this solution. These Committees could act as liaison between the students of the institutions and the Ministry of Education and if you accept this proposal, we can meet this challenge which is posed by irresponsible elements in this country.

श्री रमेशचन्द्र शंकरराव खांडेकर (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, आज हमारे देश में केवल विद्यार्थियों में ही असंतोष नहीं है, समाज के हर तबके में असंतोष है, शिक्षकों में असंतोष है, नर्सिज में असंतोष है, डाक्टरों में असंतोष है, पुलिस में असंतोष है, लाइफ इंश्योरेन्स के कर्मचारियों में असंतोष है और आम जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उसका कारण खोजने के लिए किसी भी कमीशन या किसी भी पार्लियामेंटरी कमेटी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण स्पष्ट है। स्वराज्य मिलने के 20 साल में इस शासन की जो रीति-नीति रही है वही सब इस असंतोष का कारण है।

मुझे इतना समय नहीं है कि मैं हर क्षेत्र में असंतोष क्यों है और उसके क्या उपाय किये जा सकते हैं उसके बारे में कुछ कह सकूं। मैं अपने विचार केवल शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है वहां तक ही रखूंगा। इन 19 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में जितनी खिलवाड़ इस शासन की ओर से हुई वैसी खिलवाड़ शायद किसी भी शासन ने पूरी दुनिया में नहीं की होगी। अनेकानेक प्रयोग किये गये, बेसिक एजूकेशन का प्रयोग किया गया, हाय सेकंडरी का प्रयोग किया गया। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो निवेदन सभा-पटल पर रखा उसमें कुछ झलक उन्होंने बताई, लेकिन पूरी बात नहीं थी। उनको तो चाहिए था कि पूरा विश्लेषण करें और सही-सही कारण क्या है उन्हें बताएं लेकिन शायद उनकी उतनी हिम्मत नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि 19 सालों में शिक्षा में काफी प्रगति हुई, काफी स्कूल बढ़े और शिक्षकों और विद्यार्थियों का जो अनुपात है ठीक नहीं रहा और इस वजह से विद्यार्थियों में और शिक्षकों में सम्बन्ध नहीं रहा। जिससे विद्यार्थियों में अनुशासन नहीं रहा। उन्होंने यह बात भी कही कि बड़ी-बड़ी शिक्षा संस्थानों में जो नियुक्तियां होती हैं वे भी मेरिट्स पर नहीं हो पाई। इन बीस सालों में शासकीय पार्टी ने और शासन ने शिक्षा में हस्तक्षेप किया है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर वाइस चांसलर की नियुक्ति तक में उसके तबादले के सिलसिले में या विद्यार्थियों के प्रश्नों के बारे में या स्कालरशिप के बारे में—हर क्षेत्र में बड़ा पक्षपात शासन की ओर से किया गया। वही कारण है कि आज हमारा यह देश इस अवस्था में आ गया। शिक्षा के हर क्षेत्र में आज जितना डिटेरियोरेशन हुआ, अधः पतन हुआ उसका वही कारण है। इसके लिए किसी कमीशन या पार्लियामेंटरी कमेटी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं हैं। यह सारा दोष मैं इस शासन के ऊपर मढ़ता हूं और उसी का वह परिणाम हैं कि 19 साल के बाद इस अवस्था में हम अपने को पा रहे हैं।

विद्यार्थियों का क्या दोष है ? आपने देखा होगा कि यह झगड़ा इसी साल पूरे देश में हुआ, लेकिन बार बार विद्यार्थियों के झगड़े और खासकर उत्तर हिन्दुस्तान में

काफी होते रहे । गत सितम्बर मास में जो झगड़ा हुआ उसके पहले ला ग्रेजुएट्स का आन्दोलन चल रहा था और कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ का आन्दोलन चल रहा था । मुझे नहीं मालूम यह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ का आन्दोलन और जगह था या नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में जितने एग्रीकल्चरल कालेजेज हैं उनमें स्ट्राइक चल रही थी । उनकी यह मांग थी कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में जो नया शिक्षा क्रम अमरीकी पद्धति से चालू किया है उसमें उनको असुविधा है, उसके बारे में दुबारा विचार किया जाय, लेकिन शासन कभी-कभी इतना दृढ़ नीतिवादी हो जाता है, इतना कड़ा हो जाता है कि किसी की भी सुनने को तैयार नहीं होता है । वह चल रहा था । और जगह ला के विद्यार्थियों का भी आन्दोलन चल रहा था । जब-जब एडवोकेट एमेंडमेंट बिल वहां पर लाया गया तब तब मुझे उस पर बोलने का मौका मिला था । तभी मैंने कहा था कि इस एडवोकेट एमेंडमेंट ऐक्ट को बार बार बदलना पड़ेगा । उसमें जो बातें कही गई हैं वे आप नहीं कर पायेंगे और अन्ततोगत्वा वही हुआ । ला ग्रेजुएट्स का आन्दोलन काफी बढ़ा । हर साल आन्दोलन होता था, हर साल सरकार झुक जाती थी, हर साल एमेंडमेंट होता था, हर साल एक्जेम्पशन दिया जाता था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि जो बुनियादी बात हैं उसमें कोई संशोधन करें या नहीं करें । इस समय भी विद्यार्थियों का असन्तोष भड़कने से पहले भी सरकार झुक गई और जहां तक मैंने अखबारों में पढ़ा है, बार कौंसिल की मीटिंग हुई, शिक्षा मंत्री जी भी मिले और आपस में राजीनामा होकर ला ग्रेजुएट का आन्दोलन वापस हो गया । लेकिन मैं समझता हूं कि यह पूरा समाधान नहीं है । यह शंका उस समय भी मैंने रखी थी । जब तक आप शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं करेंगे, जब तक कोई सीनियर एडवोकेटस उनको सिखाने के लिए तैयार नहीं होंगे बगैर पैसे लेकर तब तक इस प्रकार का कानून लाना गलत बात है । जैसा कि सुझाव दिया गया है, ला का कोर्स दो साल का कर लीजिए, ढाई साल का कर लीजिए, या तीन साल का कर लीजिए और उसी में एप्रेंटिसशिप रखिए, परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए । जैसे मेडिकल के ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट को डिग्री मिलती है वैसे ही ला ग्रेजुएट को भी डिग्री दी जानी चाहिए । इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

अब वह आन्दोलन जो सारे देश में भड़क उठा है उसकी शुरुआत मेरे ख्याल से हमारे मध्य प्रदेश से और ग्वालियर से हुई । मामला बहुत मामूली था । अगर थोड़े से टैक्ट से, संजीदगी से काम लिया जाता तो कोई कारण नहीं था कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश मे इस प्रकार का अन्दोलन खड़ा हो । असल में तो विद्यार्थियों को पारितोषिक दिया जाना चाहिए शिक्षा मंत्री जी या शिक्षा मंत्रालय की ओर से । बात क्या थी ? जब सरकारी सम्पत्ति का नुकसान होता है ट्रक वालों से होता है जहां पर विद्यालय है, वहीं पुलिस चौकी है । उनके विद्यालय का जो गेट था किसी ट्रक ने धक्का मार कर उसे तोड़ दिया । सरकार का करोड़ों रुपये का नुकसान होता हैं, लाखों रुपये का नकसान होता है, एक दरवाजा टूट गया, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन विद्यार्थियों की तारीफ करनी चाहिए कि जब उन्होंने देखा कि फलां ट्रक ने-- उसमें जातिवाद भी था, क्योंकि बड़ी बात बन सकती है इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ट्रक ड्राइवर और पुलिस के अधिकारी जो थे वे उसी जाति के थे--विद्यालय का फाटक तोड़ दिया तो उन्होंने इस बारे में शिकायत की । सरकार ने इन्कार किया है कि वह शराब पिए था, हो सकता है कि पिए था या नहीं पिए था लेकिन रिपोर्ट लिखने के बजाए उन्हें वहां पर

[श्री रमेशचन्द्र शंकरराव खांडेकर]

रख लिया गया, एक के साथ मार-पीट की गई ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Khandekar, you may continue later. You have spoken for ten minutes; you will have five minutes after the lunch hour.

The House stands adjourned till 2.30 in the afternoon.

The House then adjourned for lunch at half-past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Poonacha.

SHRI CHANDRA SHEKHAR (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I have to raise a point. The mover of the resolution himself is not present. When at any time a Minister is absent from the Treasury benches the whole Opposition takes a very serious view of this and I think in order to maintain the decorum and dignity of the House at least the Opposition should be a bit considerate. They should show that much courtesy to the House by being present in the House if they move a particular motion and I hope the Chair will instruct the Opposition to behave properly in the future.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Poonacha.

STATEMENT *RE.* CYCLONE WHICH PASSED OVER MADRAS ON THE 3RD NOVEMBER, 1966

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION (SHRI C. M. POONACHA): Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement regarding the cyclone that passed over Madras and the loss sustained to some vessels at the Port of Madras. [Placed in Library. *See* No. LT-7248/66.]

MOTION *RE.* WIDESPREAD UNREST AMONG STUDENTS —*contd.*

श्री रमेशचन्द्र शंकरराव खांडेकर : उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि जिस कार्य के लिये विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्रालय से इनाम मिलना चाहिये था उसके लिये उनको उसके बजाय लाठी की मार मिली । हमारे मुख्यमंत्री ने विधान सभा में प्रोवोकेटिव स्पीच दी और कहा कि थानेदार साहब को जो लाइनबन्द किया उसके लिये आपत्ति है, डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है और बिना जांच के लाइनबन्द किया गया । समय नही है नही तो मैं विस्तार में कहता । इस तरह की प्रोवोकेटिव स्पीच के बाद पुलिस को प्रोत्साहन मिला और तीन चार दिन तक ग्वालियर में और मध्य प्रदेश में जो हुआ वह पुलिस की तानाशाही थी, उसका कोई नमूना किसी डेमोक्रेसी कंट्री में देखने को नही मिलेगा । मैं स्वयं वहां पर था, मैं जेल में लोगो से मिला । हास्पिटल में गया और विद्यार्थियों से भी मिला । मेरे पास कई प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पुलिस ने बिला वजह निरपराध लोगों को मारा पीटा और जेल में बन्द किया ।

मुख्य मंत्री ने यह कहा कि इसकी जिम्मेदारी पोलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर है या एंटी-